भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1105

सोमवार, 2 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक)

महाराष्ट्र में उच्च बेरोजगारी दर

1105. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उपलब्ध वर्तमान आंकड़ों के आधार पर, पूरे देश की तुलना में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर अधिक है, जिसका मुख्य कारण बाजार की मांग के अनुरूप श्रमिकों के कौशल का न होना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोविड-19 महामारी ने राज्य के बेरोजगारी संकट को और बदतर बना दिया है और इसके परिणामस्वरूप कई उद्योगों में नौकरियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि राज्य में कई उद्योगों के लिए जिन विशेष कौशल की जरूरत है, ये कौशल नौकरी खोजने वालों में नहीं है जिससे नियोक्ताओं की मांग पूरी नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यबल को बेहतर ढंग से संगठित करने हेतु कौशल आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर **15** वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	यूआर **(%** में**)**	
	महाराष्ट्र	अखिल भारत
2017-18	4.8	6.0
2018-19	5.0	5.8
2019-20	3.2	4.8
2020-21	3.7	4.2
2021-22	3.5	4.1
2022-23	3.1	3.2
2023-24	3.3	3.2

स्रोत: पीएलएफएस

महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर वर्ष 2021 में 3.7% से घटकर वर्ष 2021-22 में 3.5% और इसके आगे वर्ष 2022-23 में 3.1% हो गई।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र सहित देश में रोजगार **2017-18** में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 16.83 करोड़ है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से, देश भर में महाराष्ट्र सहित समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध कराता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल से सुसज्जित भविष्य के लिए तैयार करने में सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए पांच योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

*****